जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

उदयपुर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 2418945 फैक्सः- 0294-2410146 वर्षः 32 संख्याः 154 प्रभात उदयपुर, मंगलवार 8 अप्रैल, 2025 आर.जे. 7202 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

8 व 9 अप्रेल को गुजरात में ए.आई.सी.सी. की बैठक है

अहम् सवाल है कि बैठक के बाद कांग्रेसाध्यक्ष खड़गे का भविष्य क्या होगा? क्योंकि, जब भी गुजरात में ए.आई.सी.सी. बैठक हुई है, उसके बाद कांग्रेसाध्यक्ष को विवादों के कारण हटना पड़ा है

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 अप्रैल। आठ और नौ अप्रैल को अहमदाबाद में एआईसीसी अधिवेशन होने जा रहा है, पर कांग्रेस पर नजदीक से नजर रखने वाले लोगों तथा विश्लेषकों के मन में एक सवाल खलबली पैदा कर रहा है कि इस एआईसीसी अधिवेशन के बाद, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भविष्य क्या होगा। यह गुजरात में आयोजित होने वाला छटा एआईसीसी अधिवेशन होगा। उल्लेखनीय है कि गुजरात में हुए विभिन्न एआईसीसी अधिवेशनों की अध्यक्षता करने वाले 5 कांग्रेस अध्यक्षों के प्रति समय उदार नहीं रहा है। या तो वे पार्टी छोड़ गये और उन्होंने अपनी स्वयं की नयी पार्टी बना ली या फिर उन्होंने स्वयं को कांग्रेस से अलग कर लिया।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसम्बर, 1885 को हुई थी।

इसका पहला अधिवेशन गुजरात के अहमदाबाद में 23-26 दिसम्बर 1902 को सुरेन्द्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। बाद में, पार्टी के अंदर पैदा हुये मतभेदों तथा उनके खिलाफ पार्टी में हुई बगावत के कारण, उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी तथा अपना नया संगठन बना लिया था।

इसके बाद, 26-27 दिसम्बर, 1907 को पार्टी का अधिवेशन सूरत में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष रास बिहारी बोस ने की थी। वे भी मतभेदों के कारण पार्टी छोड़ गये थे।

तीसरी बार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 27-28 दिसम्बर, 1921 को फिर से अहमदाबाद, गुजरात

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- गुजरात में ए.आई.सी.सी. की बैठक 1902 में हुई थी तथा बैठक के बाद अध्यक्ष सुरेन्द्र नाथ बनर्जी को हटना पड़ा था, उनके खिलाफ आंतरिक विद्रोह के कारण।
- दूसरी बार, 1907 में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में गुजरात में बैठक आयोजित हुई थी और उन्हें भी आंतरिक मतभेदों के कारण बैठक के बाद पार्टी छोड़नी पड़ी थी।
- तीसरी बार,1921 में ए.आई.सी.सी. की बैठक गुजरात में हकीम अजमल खां की अध्यक्षता में हुई थी, उनका भी वो ही हश्र हुआ था, बैठक में, जो पहले दो अध्यक्षों का हुआ था।
- चौथी बार, ए.आई.सी.सी. की बैठक 1938 में हुई, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की अध्यक्षता में। बोस ने गांधी जी के उम्मीदवार को पार्टी के आंतरिक चुनाव में हराया था तथा यह मतभेदों का बड़ा कारण बना और सुभाष बाबू को अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
- पाँचवी बार गुजरात में ए.आई.सी.सी. की बैठक नीलम संजीवा रेड्डी की अध्यक्षता में हुई तथा बैठक के बाद कांग्रेस में विभाजन हुआ और इस विभाजन के बाद नीलम संजीवा रेड्डी की संयुक्त कांग्रेस की अध्यक्षता तो खत्म होनी ही थी।
- अब छठी बार, गुजरात में ए.आई.सी.सी. की बैठक आयोजित की गई है। अतः स्वाभाविक सवाल है, इस बैठक के बाद, क्या कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पार्टी की अध्यक्षता सुरक्षित और बरकरार रहेगी तथा ऐतिहासिक परम्परा टूटेगी।

रसोई गैस महंगी हुई

नई दिल्ली, 07 अप्रैल। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को घोषणा की कि सब्सिडी वाले और गैर-सब्सिडी वाले दोनों उपभोक्ताओं के लिए 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी 8 अप्रैल से प्रभावी होगी। यह मूल्य वृद्धि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों के साथ-साथ दूसरे उपभोक्ताओं पर भी लागू होगी।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा, ''पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए कीमत 500 रुपए से बढ़ कर 550 रुपए प्रति सिलेंडर हो जाएगी। दूसरे उपभोक्ताओं के लिए यह कीमत 803 रुपए से बढ़ कर 853 रुपए हो जाएगी। संशोधन नियमित अंतराल पर की जाने वाली समीक्षा के अधीन है, जो हर दो से तीन सप्ताह में होती है।''

- सरकार ने सब्सिडी वाले एवं वगैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलैण्डरों पर 50 रु. बढ़ाने की घोषणा की।

1 अप्रैल को तेल विपणन कंपनियों ने वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत कम कर दी थी।

19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 41 रुपए की कटौती की गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में संशोधित खुदरा बिक्री मूल्य अब 1,762 रुपए प्रति सिलेंडर है।

भारत घरेलू खपत का लगभग 60 प्रतिशत एलपीजी आयात करता है। देश में एलपीजी की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार से जुड़ी हुई है।

तीन महीने में तीसरी बार राहुल गांधी बिहार पहुँचे

वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने में नीतीश की भूमिका से, कांग्रेस का मानना है, मुस्लिम मतदाता नीतीश कुमार से रुष्ट हैं, तथा और दूर हो जाएंगे

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 अप्रैल। जिन दो राज्यों में कांग्रेस तीन दशक पहले अपनी प्रभावी स्थिति खो चुकी है, उन राज्यों में पार्टी का पुनरोद्धार करने तथा उसे एक नया रुप देने के उद्देश्य से, राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व ने उन राज्यों पर अपनी नजरें जमा रखी हैं। इन राज्यों में से एक, भाजपा-शासित गुजरात, में कांग्रेस ने अपनी वर्किंग कमेटी की मीटिंग आयोजित करने का निर्णय लिया है। और दूसरा राज्य चुनावाधीन बिहार है, जहाँ राहुल गांधी पिछले तीन महीनों में आज तीसरी बार दौरे पर गये हैं।

वक्फ विधेयक पारित होने के बाद, विपक्षी गठबंधन बिहार के आगामी चुनावों में अपने अवसर के सपने सँजो रहा है। ज्ञातव्य है कि बिहार में मुस्लिम मतदाता, राज्य के कुल मतदाताओं के 17 प्रतिशत हैं।

जातिगत जनगणना तथा पिछड़ा वर्ग-समर्थन के अभियान को जारी रखते हुये, राहुल ने आज पटना में एक विचार गोष्ठी को सम्बोधित किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की पूर्ववर्ती असफलताओं से सबक लेते हुये, पुरानी गलतियों को सुधारने की बात कही। उन्होंने कहा कि वे इस गलती को स्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति होंगे कि पार्टी राज्य का बहुमुखी विकास करने में असफल रही तथा पार्टी ने दलित वर्गों के सशक्तीकरण के मामले में शिथिलता एवं लापरवाही बरती। राहुल ने कहा, ''हमने अपेक्षित उत्साह से काम नहीं किया। लेकिन हम बिहार में हुईं अपनी गलतियों से सबक ले रहे हैं तथा हम, अपने गठबंधन पार्टनरों के साथ आगे बढ़ेंगे, और एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी एवं अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिये काम करेंगे।'' इससे पहले, राहुल ''पलायन रोको, नौकरी दो'' पद यात्रा में शामिल होने बेगूसराय गये थे। इस पद यात्रा का आयोजन पार्टी की युवा एवं विद्यार्थी शाखा ने किया था, ताकि बिहार की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- कांग्रेस का सोच है, मुस्लिम मतदाता, जो बिहार में लगभग 17 प्रतिशत हैं, अब कांग्रेस की ओर आएगा, तथा जातिगत मतगणना तथा बैकवर्ड समर्थन सोच के कारण कांग्रेस बिहार में अच्छी स्थिति में रहेगी।
- इस सोच में कांग्रेस का इतना विश्वास है, कि राहुल गांधी अब सार्वजनिक रुप से स्वीकार करने लगे हैं, कि उनकी पार्टी बैकवर्ड जातियों के विकास के लिये पूर्ण जोश व उत्साह से काम करने में चूक गई थी।
- राहुल गांधी ने पटना में एक सिमपोज़ियम को सम्बोधित करते हुए पार्टी की पुरानी गलती स्वीकार की।
- बेगूसराय में, जो एनएसयूआई अध्यक्ष, कन्हैया का घर भी है, राहुल ने नारा दिया, ''पलायन रोको, नौकरी दो'', और उन्होंने बिहार का पुराना रोग, बेरोजगारी व ''माइग्रेशन'' (पलायन) को हाई-लाइट किया।

तेलंगाना के मु.मंत्री को भारी पड़ा, लोकप्रिय फिल्म एक्ट्रेस पर झूठा आरोप लगाना

रैवन्त रेड्डी ने दिया मिर्ज़ा पर आरोप लगाया कि उन्होंने ए.आई. जैनरेटेड फोटोग्राफ लगायीं, आंदोलन का ''हौव्वा'' दिखाने के लिए

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 अप्रैल। तेलंगाना के मुख्यमंत्री एक ''चार्मर'' हैं जल्दी ही लोगों को लुभा लेते हैं और मीडिया तथा अन्य कथानकों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने में माहिर हैं पर सैलिब्रिटीज़ पर कंचा गाचीबोवली जंगल पर फक न्यूज़ व एआई से बने वीडियो फैलाने का आरोप लगाकर उन्होंने खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर ली है।

बेहद साहसी सेलिब्रिटीज़ में से एक दिया मिर्ज़ा, जो हैदराबाद से ही हैं, ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और रैवन्त रेड्डी की इस बात के लिए कड़ी निंदा की क्योंकि इन्होंने उन पर झूठे एआई वीडियो व फोटो फैलाने का झूठा आरोप लगाया। दिया मिर्ज़ा ने 400 एकड़ वन भूमि, जिसे सरकार नीलाम करना चाहती है, से पेड़ काटने के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों के पक्ष में कुछ वीडियो व तस्वीरें पोस्ट की है। रेड्डी का आरोप है कि ये वीडियो व तस्वीरें एआई से तैयार हैं। फिल्म स्टार दिया मिर्ज़ा, जो संवेदनशील किरदारों और शानदार अभिनय के लिए जानी जाती है, ने अपने एक्स एकाउण्ट पर रैवन्त रेड्डी के आरोपों को ''पूरी तरह से झूठ'' करार दिया और कहा कि मैंने एआई जनरेटेड फोटो व वीडियो का इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कल एक ट्वीट किया जिसमें कंचा गाचीबोवली के बारे में कुछ दावे किए उनमें एक था कि 400 एकड़ जमीन, जिसे सरकार बेचना चाहती है, की जैवविविधता को बचाने के विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के पक्ष में मैंने फेक एआई जनरेटेड फोटो व वीडियो पोस्ट किए हैं। यह एक गलत बयान है मैंने ऐसी एक भी तस्वीर या वीडियो पोस्ट नहीं किया है जो एआई से तैयार किया गया हो।

अभिनेत्री ने मीडिया और राज्य सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा, ''मीडिया और तेलंगाना सरकार को ऐसे दावे करने से पहले अपने तथ्यों की जांच करनी चाहिए।''

सोशल मीडिया पर कंचा गाचीबोवली में पेड़ों को गिराने से

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- दिया मिर्ज़ा ने कड़ा विरोध किया कि मु.मंत्री को तथ्य जान लेने चाहिए, कोई आरोप लगाने से पहले।
- अन्य फिल्म हस्तियों, जैसे, जॉन अब्राहम, रवीना टण्डन ने भी दिया मिर्ज़ा का पूर्ण समर्थन किया।

पुनर्गठन व परिसीमन के बाद पंचायत चुनाव कार्यक्रम तय होगा

जयपुर, 7 अप्रैल। प्रदेश की 6759 पंचायतों के चुनाव स्थगित कर, निवर्तमान सरपंचों को प्रशासक बना दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका में राज्य सरकार ने सोमवार को हाईकोर्ट में अतिरिक्त शपथ पत्र पेश किया है। वहीं, सोमवार को मामले का नंबर नहीं आने के कारण मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस आनंद शर्मा की बैंच में मामले की चल रही सुनवाई दो सप्ताह के लिए टल गई है।

राज्य सरकार की ओर से पेश शपथ पत्र में कहा गया कि पंचायतों और नगरपालिकाओं के पुनर्गठन व परिसीमन के लिए मार्च महीने में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह प्रक्रिया मई-जून महीने तक चलेगी और उसके बाद ही पंचायतों का चुनाव कार्यक्रम तय किया जाएगा। दरअसल, गिर्राज सिंह व अन्य की पीआईएल में पिछली सुनवाई पर खंडपीठ ने राज्य सरकार व चुनाव आयोग से पूछा था कि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में अतिरिक्त शपथ पत्र पेश कर यह जानकारी दी।

स्टालिन तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव, मोदी बनाम स्टालिन संघर्ष बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं

ममता बनर्जी की भांति स्टालिन का भी तमिलनाडु के मीडिया पर पूरा कंट्रोल है तथा वो स्थानीय मीडिया का एजेण्डा निर्धारित कर रहे हैं

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 अप्रैल। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रमुक प्रमुख एम.के. स्टालिन ने खुद को सीधे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मुकाबले में खड़ा कर दिया है। वे खुद को ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं, मानो सीधे प्रधानमंत्री को चुनौती दे रहे हैं, जैसे प.बंगाल में ममता बनर्जी दे रही हैं, जहाँ अगले वर्ष चुनाव हो रहे हैं। उन्होंने तमिलनाडु के पबंन ब्रिज के उद्घाटन समारोह में भाग नहीं लिया। इस पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया था। इसके बाद अन्नामलाई के नेतृत्व में भाजपा नेताओं ने हगांमा शुरु कर दिया और आरोप लगाने लगे कि स्टालिन ने उद्घाटन समारोह में भाग न लेकर प्रधानमंत्री का अपमान किया है। यही नहीं, जब प्रधानमंत्री राज्य में आए तो स्टालिन ने उनका स्वागत तक नहीं किया। उनकी बजाय उपमुख्यमंत्री पी. त्यागराजन ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री स्टालिन जो भी करते है या कर रहे हैं, उसमें पूरी सोची समझी रणनीति होती है। वे पूरे विषय को खुद के और प्रधानमंत्री के मुकाबले में बदल देते हैं। स्टालिन ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने काचातीवू द्वीप वापस लेने की तमिलनाडु की मांग की उपेक्षा की है। स्टालिन के शब्दों से ऐसा लगता है, जैसे यह समस्या मोदी सरकार की देन है। स्टालिन ने कहा कि केन्द्र सरकार और मोदी तमिल विरोधी हैं।

प्रसंगवश बता दें कि स्टालिन द्वारा उठाये गये अधिकांश मुद्दे भावनात्मक है, जिन्होंने प्रधानमंत्री तथा भाजपा को तमिल-विरोधी रूप में चित्रित करने में स्टालिन की मदद की है। इन मुद्दों में शामिल हैं- भाषा का मुद्दा, परिसीमन का मुद्दा, तमिलनाडु के विद्यार्थियों को नीट से छूट दिये जाने की तमिलनाडु की माँग को खरिज किया जाना और अब वक्फ विधेयक का पारित होना।

राज्य को शिक्षा-फंड जारी करने से केन्द्र के इनकार को भी द्रमुक तथा उसका प्रचार-तंत्र, तमिलनाडु के प्रति केन्द्र के सौतेले व्यवहार के एक और उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। ज्ञातव्य है कि द्रमुक का प्रचार तंत्र, कम से कम तमिलनाडु में तो, भाजपा के प्रचार तंत्र से कम नहीं पड़ता, बल्कि उसे पछाड़ने की कुव्वत रखता है।

ठीक पश्चिम बंगाल की तरह, जहाँ स्थानीय मीडिया पर ममता बनर्जी तथा उनकी पार्टी की पूरी पकड़ है, तमिलनाडु में द्रमुक के अपने स्वयं के बहुत ताकतवर मीडिया ब्रान्ड हैं तथा द्रमुक की मीडिया-प्रबंधन रणनीति पूरी तरह अभेद्य है।

इस क्षेत्रीय दल के पास इस मामले में जो ताकत है, उसका उसके राष्ट्रीय पार्टनर, कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर अभाव साफ दिखाई देता है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- मोदी बनाम स्टालिन का वातावरण बनाने के लिए उन्होंने स्थानीय मुद्दे, डीलिमिटेशन, नई शिक्षा नीति, नीट परीक्षा का विरोध आदि मुद्दे उठाए और अब प्र.मंत्री मोदी की तमिलनाडु यात्रा में भी वे न प्र.मंत्री का स्वागत करने हवाई अड्डे गये और न ही प्र.मंत्री के समारोह में शरीक हुए।
- वे तमिलनाडु के पुराने मुद्दों को भी, जैसे काचातीवू टापू के विवाद को, ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे कि यह मोदी के सत्ता में आने से पैदा हुआ है।

'क्या कार्यवाही शुरु कराने के लिए हर बार एसपी को बुलायें'

जयपुर, 7 मार्च। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में लापता नाबालिगों की बरामदगी नहीं होने के मुद्दे पर गंभीर टिप्पणी की, उस समय डीजीपी भी मौजूद थे। अदालत ने कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं में हम पहले थानाधिकारी को बुलाते हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। वहीं, जैसे ही संबंधित एसपी को बुलाते हैं तो मामले में कार्रवाई शुरू हो जाती है। कई मामलों में तो लापता की बरामदगी भी हो जाती है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस मुकेश राजपुरोहित ने यह टिप्पणी नाबालिग लापताओं के चार मामलों में सुनवाई करते हुए की।

सुनवाई के दौरान, डीजीपी यूआर साहू अदालत में पेश हुए। उनके साथ

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- हाई कोर्ट ने लापता नाबालिगों के चार मामलों में डीजीपी यू.आर. साहू को बुलाकर तीखी टिप्पणी की।

चीन, यूरोपियन यूनियन, कैनडा, मैक्सिको आदि सभी देश अमेरिका को सबक सिखाने के मूड में

यूरोपियन यूनियन, चीन, कैनडा, मैक्सिको ने अमेरिका से इन देशों को निर्यात होने वाले सामान पर भारी टैरिफ वृद्धि जड़ी

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 अप्रेल। ट्रंप की टैरिफ तथा ट्रेड की गलाघोंटू वाणिज्यिक व व्यापारिक नीतियों के कारण एक ग्लोबल इकोनॉमिक वॉर छिड़ गया है, जिसमें सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं नए अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को सबक सिखाने के लिए सख्त कदम उठा रही हैं। टैरिफ (शुल्क) एक दोधारी तलवार की तरह है। यदि आप दूसरों पर शुल्क लगाते हैं तो वो भी आपके खिलाफ समान या और अधिक कठोर कदम उठा सकते हैं।

इसका परिणाम, बढ़ती महँगाई, घटता व्यापार, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मंदी, लोगों की आय में गिरावट और भारी बेरोजगारी हो सकता है।

ट्रंप द्वारा रैसिप्रोकल टैरिफ लगाने के बाद सोमवार को जब स्टॉक मार्केट खुले तो विश्व भर के स्टॉक बाज़ारों में भारी तबाही का मंजर देखने को मिला। स्टॉक मार्केट ''बेयर मार्केट'' की स्थिति में हैं, जिसका अर्थ है कि इस समय इन्वैस्टर अपना इन्वैस्टमैंट बेचकर नकदी रखना पसंद करेंगे, बजाय स्टॉक्स में पैसा लगाने के।

जापान का स्टॉक मार्केट, जो दुनिया के सबसे बड़े बाज़ारों में एक है, टैरिफ वॉर के कारण सोमवार को 8 प्रतिशत गिर गया। भारत के स्टॉक मार्केट में 2227 पॉइन्ट की गिरावट आई, जिसने 14 लाख करोड़ रूपए की शेयर वैल्यू को मिटा दिया। चीन का शेयर बाज़ार भी गिरा। यूरोपीय बाज़ार को 10 प्रतिशत की गिरावट के बाद 1.7 ट्रिलियन यूरो का नुकसान झेलना पड़ा।

बाजारों की इस उथल-पुथल के बीच, 29 देशों वाली यूरोपियन यूनियन (ई.यू.) ने ट्रंप के पिछले सप्ताह के शुल्कों के जवाब में अपने खुद के शुल्कों की घोषणा की। यूरोपीय संघ ने अमेरिका से आयात पर 28 बिलियन डॉलर के शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा। ई.यू. के व्यापार आयुक्त ने कहा कि ये शुल्क 9 अप्रैल से प्रभावी होंगे।

चीन, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जिसे ट्रंप ''नम्बर वन'' दुश्मन मानते हैं, ने अमेरिका से आयात पर 34 प्रतिशत से अधिक शुल्क लगाने की घोषणा की है। अब चीन अमेरिका से आयात पर अपने शुल्कों को और बढ़ाने और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है।

अमेरिका के रैसिप्रोकल टैरिफ और अन्य टैक्स, जिसमें 10 प्रतिशत का बेसिक टैक्स भी शामिल है, के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- यूरोपीय देशों ने 28 अरब डॉलर का आयात शुल्क लगाया।
- चीन ने 34 प्रतिशत का टैरिफ लगाया अमेरिकी सामान पर।
- ये देश, टैरिफ युद्ध में इसलिये उतरे कि अमेरिका के टैरिफ धमाकों से इन सभी देशों के स्टॉक एक्सचेंज में शेयर की कीमतों में गिरावट आई
- जापान के स्टॉक एक्सचेंज में 8 प्रतिशत की गिरावट आई, चीन के स्टॉक मार्केट में दस प्रतिशत टूट हुई। जैसा कि विदित ही है अमेरिका ने चीन के माल पर 54 प्रतिशत का टैरिफ लगाया है।
- जे.पी. मॉर्गन बैंक (अमेरिका) के अध्यक्ष जैमी डीमॉन ने शेयर होल्डर्स को संबोधित करते हुए कहा, अमेरिका की विशेष पोज़िशन थी, विश्व में, अपनी इकोनॉमी की ताकत, सेना के ''पावर'' और अपनी नैतिक मान्यताओं के कारण, जिसका मुख्य हिस्सा थी इकोनॉमी व राजनीति में स्वतंत्रता, पर, अब यह मान्यता खत्म हो रही है।

एकल पट्टा प्रकरण में अशोक पाठक को पक्षकार बनाने पर बहस जारी

जयपुर, 7 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट में सोमवार को पूर्व मंत्री शांति धारीवाल से जुड़े चर्चित एकल पट्टा मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता रहे अशोक पाठक को पक्षकार बनाए जाने के मुद्दे पर बहस जारी रही। अदालत मामले में मंगलवार को सुनवाई करेगी।

मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव की एकलपीठ के समक्ष पूर्व मंत्री धारीवाल के अधिवक्ता वीआर बाजवा ने पाठक को पक्षकार बनाए जाने पर आपत्ति जताई। बाजवा ने कहा कि अशोक पाठक मामले में न तो शिकायतकर्ता हैं और न ही उनके कोई हित प्रभावित हुए हैं। ऐसे में उनका इस केस से कोई संबंध नहीं है। जवाब में पाठक के अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- पूर्व मंत्री धारीवाल के अधिवक्ता ने पाठक को पक्षकार बनाने पर आपत्ति की।